(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन हेतु सौर प्रकाशवोल्टीय (एस.पी.वी.) कार्यक्रम शुरू किया गया है जो उत्तर प्रदेश अपारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है । इस एजेंसी ने गांवों में छोटे गांव स्तर के एस.पी.वी. विद्युत संयंत्रों की संस्थापना के लिए विभिन्न जिलों में गांव स्तर पर सर्वेक्षण किए हैं, जो कि बिजली ग्रिडों से विशेष रूप से दूर हैं और जिनके पारंपरिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के माध्यम से अगले 5–10 वर्षों के दौरान विद्युतीकरण होने की संभावना नहीं है । अब तक 34 विद्युत संयंत्र संस्थापित किए गए हैं और राज्य में 31 संयंत्र कार्यान्वयनाधीन हैं ।

लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

476. **श्री विमलभाई हरिभाई शुक्ल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान 1000 लघु जल-विद्युत परियोजनायें स्थापित करने का निर्णय लिया है ;

(ख) क्या इस संबंध में अधिकांश राज्यों ने संयुक्त उद्यम में अपनी रुचि दिखलाई है ;

(ग) क्या डी.ई.पी.ए. की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई थी ;

(घ) उस विशेष रिपोर्ट में किन-किन मुख्य बातों का उल्लेख किया गया था; और

(ङ) किन-किन राज्यों में इस प्रकार की परियोजनायें स्थापित किए जाने का विचार है ?

गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) (क) जी, नहीं । तथापि, इस मंत्रालय द्वारा आठवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान तय किया गया 600 मे.वा. का लक्ष्य लगभग 1000 लघु पन-बिजली विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है । ये परियोजनायें राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों अथवा निजी क्षेत्र को शामिल करके स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ।

(ख) संसाधनों में वृद्धि करने और लघु पन-बिजली परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों द्वारा संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियां बनाने की अवधारणा की जांच की जा रही है । तथापि, यह निवेश वातावरण और राज्य सरकारों की समग्र नीतियों पर निर्भर करेगा ।

(ग) और (घ) जी, नहीं । इस मंत्रालय द्वारा न तो ऐसी किसी विशेषज्ञ समिति की स्थापना की गई है और न ही इस मंत्रालय को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ।

(ङ) इन परियोजनाओं की संभाव्यता और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाने की संभावना है

मध्य प्रदेश में गैर परम्परागत स्रोतों से बिजली उत्पादन

477. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में गैर-परम्परागत स्रोतों से बिजली का उत्पादन करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश को इस उद्देश्य के लिए कितनी

धनराशि प्रदान की गई और इस संबंध में क्या उपलब्धि रही है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

गर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार): (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय देश भर में, जिसमें मध्य प्रदेश शामिल है, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन, बायोमास, लघु पन बिजली आदि से बिजली उत्पादन के लिए बहुत से कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। मध्य प्रदेश राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विभिन्न बिजली उत्पादन प्रणालियों/परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। (नीचे देखिए) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य को 743.95 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

(ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से राज्यवार-लक्ष्य अग्रिम रूप से निर्धारित नहीं किए जाते हैं परन्तु परियोजनाओं पर प्रत्येक मामले के आधार पर विचार किया जाता है।

विवरण

मध्य प्रदेश राज्य में संस्थापित बिजली उत्पादन की एन. आर. एल. ई. प्रणालियों की सूची

क्रम सं.	प्रणाली/परियोजना का नाम	संख्या
1.	जिला बेतुल म. प्र. में खेडा स्थित पवन फार्म परियोजना	1 (0.59 मे. वा.)
2.	सौर प्रकाश वोल्टीय रोशनी प्रणालियां	5427
3.	सौर लालटैन	750
4.	एस. पी. वी. घरेलू प्रकाश	100
5.	सौर सामुदायिक टेलीविजन	46
6.	एस. पी. वी. विद्युत संयंत्र	1 (6 के. डब्लू पी.)
7.	बायोमास गैसीफायर	10 (100 के. डब्ल्यू पी)
8.	लघु पन-बिजली परियोजना	6 (7.05 मे. वा.)*

*संस्थापनाधीन

पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन

478. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पवन ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करने के लिए गुजरात के कच्छ जिले के मुन्द्रा और कुकया क्षेत्रों में कतिपय परीक्षण किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है और चालू/आगामी वित्तीय वर्ष में इस के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है दिए जाने का विचार है?